



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 523 ]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 9, 2000/आश्विन 17, 1922

No. 523 ]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 9, 2000/ASVINA 17, 1922

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2000

सा.का.नि. 778(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (घख) के साथ पठित धारा 14ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तों) नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) “अपील अधिकरण” से अधिनियम की धारा 14 के अधीन स्थापित दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) “अध्यक्ष” से अधिनियम की धारा 14ख(1) के अधीन नियुक्त किया गया अपील अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) “सदस्य” से अधिनियम की धारा 14ख(1) के अधीन नियुक्त किया गया अपील अधिकरण का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(ङ) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

3. अध्यक्ष का वेतन, भत्ते आदि—(1) (क) अध्यक्ष के रूप में, यदि उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तो वह मासिक वेतन, और ऐसे भत्ते तथा अन्य प्रसुविधाएं प्राप्त करने का हकदार होगा, जो उच्चतम न्यायालय के किसी सेवारत न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं।

(ख) अध्यक्ष के रूप में, यदि किसी उच्च न्यायालय का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त किया जाता है तो वह मासिक वेतन, और ऐसे भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं प्राप्त करने का हकदार होगा जो अपील प्राधिकरण के मुख्यालय स्थान पर उच्च न्यायालय के सेवारत मुख्य न्यायाधिपति को अनुज्ञेय है।

परन्तु यदि उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिपति पेंशन, उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या अन्य प्रकार की सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के रूप में कोई सेवानिवृत्ति प्रसुविधा प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने के लिए पात्र हो गया है, ऐसी दशा में उक्त अध्यक्ष के वेतन में से, इसके द्वारा आहरित की गई या आहरित की जाने वाली पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य प्रकार की सेवानिवृत्ति प्रसुविधा की सकल राशि, यदि कोई है (उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर) कम कर दी जाएगी।

4. छुट्टी—(1) यदि सेवा निवृत्त हो चुका उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, वह सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन की उपार्जित छुट्टी का हकदार होगा और अध्यक्ष की छुट्टी मंजूर करने के लिए भारत के राष्ट्रपति सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(2) छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का संदाय, केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 द्वारा शासित होगा।

(3) अध्यक्ष, किसी भी समय अपने खाते में जमा उपार्जित छुट्टी का पचास प्रतिशत भुनाने का हकदार होगा।

5. अभिदायी भविष्यनिधि में अभिदाय—यदि कोई सेवानिवृत्त हो चुका उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश/उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, वह अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाय करने का हकदार होगा जो अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 द्वारा शासित होगा।

6. सेवा की अन्य शर्तें : अध्यक्ष की सेवा शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 और उस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं अन्य नियमों, या उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम, 1954, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1956 या उस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी अन्य नियम द्वारा शासित होंगे :

परन्तु देश के भीतर शासकीय दौरे पर रहने के दौरान सरकारी वास सुविधा उपलब्ध नहीं होने की दशा में, अध्यक्ष, भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में प्रतिपूर्ति के आधार पर और जहां भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल उपलब्ध नहीं हैं वहां अन्य होटलों में प्रतिपूर्ति के आधार पर रुकने के हकदार होंगे, दोनों दशाओं में प्रतिपूर्ति केवल वास प्रभावों तक और एकल कमरा अधिभोग के आधार पर सीमित होगी।

7. नियमों का लागू होना—यदि उच्चतम न्यायालय को कोई सेवारत न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई सेवारत मुख्य न्यायाधिपति अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें वही होगी, जो अध्यक्ष के रूप में उसकी सेवा नियुक्ति से पूर्व उसे लागू थीं;

परन्तु अध्यक्ष के रूप में उसकी अवधि के अवसान से पूर्व न्यायाधीश के रूप में अध्यक्ष की अधिवर्षिता की दशा में सेवा की शेष अवधि के दौरान उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें, इन नियमों के अधीन वही होंगी, जो यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिपति को लागू होती है।

8. सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें :—(1) अपील अधिकरण के सदस्य निम्नलिखित प्राप्त करने के हकदार होंगे :—

(i) प्रतिमास 26,000/- रु. वेतन (स्थिर) और समतुल्य वेतन आहरित कर रहे केन्द्रीय सरकार के समूह “क” अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर मंहगाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्तु सदस्य के रूप में नियुक्त ऐसे व्यक्ति की दशा में जो, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है और जो पेंशन, उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या अन्य प्रकार की सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के रूप में कोई सेवानिवृत्ति प्रसुविधा प्राप्त कर रहा है, या प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार है, ऐसे सदस्यों के वेतन में से उसके द्वारा आहरित की गई या आहरित की जाने वाली पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य प्रकार की सेवानिवृत्ति प्रसुविधा की सकल राशि, यदि कोई है (उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़ कर), कम कर दी जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि कोई व्यक्ति सेवा से, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या स्वशासी निकायों के अधीन सेवा भी है, सेवानिवृत्त हो गया है और सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, वह उसी दर पर मंहगाई भत्ता प्राप्त करेगा जो समतुल्य वेतन आहरित करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह “क” अधिकारी को अनुज्ञेय है, लेकिन वह ऐसे सदस्य के रूप में उसके पद धारण करने की अवधि के दौरान पेंशन पर मंहगाई राहत प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(ii) नगर प्रतिकारात्मक भत्ता उसी दर पर, जो केन्द्रीय सरकार के अधीन समतुल्य वेतन आहरित कर रहे समूह “क” अधिकारी को अनुज्ञेय है, प्राप्त करने का हकदार होगा।

(iii) (क) सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन की उपार्जित छुट्टी के हकदार होंगे और छुट्टी के दौरान छुट्टी के वेतन का संदाय केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा और सदस्यों की छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष होगा।

(ख) किसी भी समय उसके खाते में जमा उपार्जित छुट्टी के पचास प्रतिशत को भुनाने के हकदार होंगे।

(iv) अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाय करने के हकदार होंगे जो अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 द्वारा शासित होगा;

(v) दौरे पर रहने के दौरान या स्थानांतरण होने पर निजि चीज-बस्त के परिवहन (जिसके अन्तर्गत अपील अधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने या अपील अधिकरण में अपनी अवधि का अवसान हो जाने पर अपने स्वंगर के लिए की गई यात्रा भी है) के लिए उम्मीद से यात्रा-भत्ता और दैनिक-भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो समतुल्य वेतन आहरित कर रहे केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं;

(vi) दौरे पर रहने के दौरान, बाहरी स्थानों पर सरकारी वास-सुविधा, उपलब्ध होने पर, सरकार द्वारा चलाए जा रहे अतिथि-गृहों या निरीक्षण बंगलों में, सामान्य किराया संदत्त करने पर प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो समतुल्य वेतन आहरित कर रहे केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं;

परन्तु यदि देश के भीतर दौरे पर रहने के दौरान सरकारी वास-सुविधा उपलब्ध नहीं है तो सदस्य, भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में प्रतिपूर्ति के आधार पर और जहाँ कहीं भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल उपलब्ध नहीं हैं, अन्य होटलों में प्रतिपूर्ति के आधार पर ठहरने के लिए हकदार होंगे, दोनों दशाओं में प्रतिपूर्ति केवल वासा प्रभागों तक और एकल कमरा-अधिभोग के आधार पर सीमित रहेगी;

(vii) छुट्टी यात्रा रियायत उसी दर पर प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो समतुल्य वेतन आहरित कर रहे केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं;

(viii) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम में यथा उपबंधित चिकित्सीय उपचार और अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार होंगे और जिन स्थानों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम प्रचालन में नहीं है, सदस्य केन्द्रीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 में यथा उपबंधित सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार होंगे;

(ix) दूरसंचार विभाग में भारत सरकार के भारसाधक मंत्री के पूर्व अनुमोदन और राजनीतिक मामलों से संबंधित विषयों पर विदेश मंत्रालय से समाशोधन के पश्चात् विदेशों में शासकीय रूप में भ्रमण करने के हकदार होंगे, विदेश दौरे की अवधि के दौरान दैनिक भत्ता और होटल में वास-सुविधा की व्यवस्था भारत सरकार के समान श्रेणी के अधिकारियों को लागू सरकार के अनुदेशों के अनुसार विनियमित होगी; विदेश में भारतीय मिशन इंतजामों की देख-रेख करेंगे और वैसे ही सुविधाएं देंगे जो समतुल्य वेतन आहरित कर रहे केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं।

(x) उसी प्रकार वाहन सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसे कि समतुल्य वेतन आहरित कर रहे केन्द्रीय सरकार के समूह "क" के अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं।

(xi) आवासीय वास-सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसे कि समतुल्य वेतन आहरित कर रहे केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय है और पद त्याग करने पर, सदस्य, उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर एक मास के लिए आवासीय वास-सुविधा प्रतिधारित करने का हकदार होगा।

(2) सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति—कोई व्यक्ति, जो सरकारी सेवा में है, सदस्य के रूप में उसका चयन किए जाने पर उसे, सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, सेवा से सेवानिवृत्त होना पड़ेगा।

#### 9. पद और गोपनीयता की शपथ :—

अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व इन नियमों के साथ उपाबद्ध क्रमशः प्ररूप I और प्ररूप II में, पद की और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा।

10. वित्तीय या अन्य हित की घोषणा—प्रत्येक व्यक्ति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में, यथास्थिति, उसके नियुक्त किए जाने पर, केन्द्रीय सरकार का समाधान करने के लिए, इन नियमों के साथ उपाबद्ध प्ररूप III में यह घोषित करेगा कि उसका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में, यथास्थिति, उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

#### 11. अवशिष्ट उपबंध :

अध्यक्ष या सदस्य की सेवा के निबंधनों और शर्तों से संबंधित ऐसे विषयों के प्रति जिनकी बाबत इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, अपील अधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्देश किया जाएगा।

12. शिथिल करने की शक्ति :—केन्द्रीय सरकार को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत इन नियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल करने की शक्ति होगी।

[फा.सं. 10-11/2000-टीसीओ]

अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

## प्ररूप-I

(नियम 9 देखें)

दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए पद की शपथ का प्ररूप

मैं, ----- अध्यक्ष/सदस्य  
(जो लागू नहीं हो उसे काट दें) के रूप में नियुक्त किए जाने पर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ और ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य (जो लागू नहीं हो उसे काट दें) के रूप में अपने कर्तव्यों का, भय या पक्षपात, अनुराग या वैमनस्य के बिना, अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेकबुद्धि से निष्ठापूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से, निर्वहन करूँगा।

तारीख :

(अध्यक्ष/सदस्य का नाम)

दूरसंचार विवाद समाधान और  
अपील अधिकरण

## प्ररूप-II

(नियम 9 देखें)

दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए गोपनीय पद की शपथ का प्ररूप

मैं, ----- अध्यक्ष/सदस्य  
(जो लागू नहीं हो उसे काट दें) के रूप में नियुक्त किए जाने पर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ और ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं कोई बात, जो दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य (जो लागू नहीं हो उसे काट दें) के रूप में मेरे विचाराधीन होगी या मुझे ज्ञात होगी, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को अध्यक्ष/सदस्य (जो लागू नहीं हो उसे काट दें) के रूप में अपने कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यकता पड़ने की दशा को छोड़कर, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।

तारीख :

(अध्यक्ष/सदस्य का नाम)

दूरसंचार विवाद समाधान और  
अपील अधिकरण

## प्ररूप-III

(नियम 10 देखें)

किसी प्रतिकूल वित्तीय या अन्य हित के अर्जन के विरुद्ध घोषणा

मैं, ----- दूरसंचार विवाद समाधान  
और अपील अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य (जो लागू नहीं हो उसे काट दें) के रूप में नियुक्त किए जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मेरा इस समय कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है न ही भविष्य में होगा, जिसके कारण दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य (जो लागू नहीं हो उसे काट दें) के रूप में मेरे कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

तारीख :

(अध्यक्ष/सदस्य का नाम)

दूरसंचार विवाद समाधान और  
अपील अधिकरण

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS****(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th October, 2000

**G.S.R. 778(E).**—In exercise of the powers conferred by section 14E read with clause (db) of sub-section (2) of Section 35 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

**1. Short title and commencement** - (1) These rules may be called the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions** - In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Act” means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);
- (b) “Appellate Tribunal” means the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal established under section 14 of the Act;
- (c) “Chairperson” means the Chairperson of the Appellate Tribunal appointed under section 14 B(1) of the Act;
- (d) “Member” means a Member of the Appellate Tribunal appointed under section 14 B(1) of the Act;
- (e) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Salary, allowances, etc. of the Chairperson** :- (1)(a) When a serving or a retired Judge of the Supreme Court is appointed as Chairperson, he shall be

entitled to a monthly salary, and to such allowances and other benefits, as are admissible to a serving Judge of the Supreme Court.

(b) When a serving or a retired Chief Justice of a High Court is appointed as Chairperson, he shall be entitled to a monthly salary and to such allowances and other benefits as are admissible to a serving Chief Justice of the High Court of the Headquarter station of the Appellate Tribunal.

Provided that in case the retired Judge of the Supreme Court or the retired Chief Justice of a High Court, is in receipt of, or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employers contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Chairperson shall be reduced by the gross amount of pension or employers contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any (except pension equivalent of gratuity), drawn or to be drawn by him.

**4. Leave -** (1) When a retired Supreme Court Judge or a Chief Justice of High Court is appointed as Chairperson, he shall be entitled to 30 days of Earned Leave for every year of service and the President of India shall be the authority competent to sanction leave to the Chairperson.

(2) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(3) The Chairperson shall be entitled to encashment of fifty per cent of Earned Leave to his credit at any time.

**5. Contribution to Contributory Provident Fund** -When a retired Supreme Court Judge/ Chief Justice of High Court is appointed as Chairperson, he shall be entitled to subscribe to the Contributory Provident Fund which shall be governed by the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962.

**6. Other conditions of service:** The conditions of service of Chairperson for which no provision is made in these rules shall be governed by the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958, Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959 and any other rules made under the Act, or the High Court Judges Act, 1954, High Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1956 and any other rule made under the Act, as the case may be:

Provided that in case Government accommodation is not available while on domestic official tour, the Chairperson shall be entitled to stay in India Tourism Development Corporation hotels on a reimbursement basis and wherever India Tourism Development Corporation hotels are not available, in other hotels on

reimbursement basis, reimbursement in both cases being limited to lodging charges only, and on a single room occupancy basis.

**7. Applicability of rules -** When a serving Judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court is appointed as the Chairperson, his terms and conditions of service shall be the same as were applicable to him prior to his appointment as the Chairperson:

Provided that in case of superannuation of Chairperson as Judge before the expiry of his term as Chairperson, his terms and conditions of service shall be the same as are applicable to a retired Judge of the Supreme Court or a retired Chief Justice of a High Court, as the case may be, under these Rules, for remainder period of his term.

**8. Terms and Conditions of Service of Members - (1)** The Members of the Appellate Tribunal shall be entitled to—

(i) receive a pay of Rs.26,000/- per month (fixed) and dearness allowance at the rate admissible to a Group 'A' officer of the Central Government drawing an equivalent pay:

Provided that in case of appointment of a person as a Member who has retired from the service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of, or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employers contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Member shall be reduced by the gross amount of pension or employers contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any (except pension equivalent of gratuity), drawn or to be drawn by him:

Provided further that if a person who has retired from any service including service under Central Government or State Government, Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies, is appointed as a Member, he shall receive dearness allowance at the same rate as is admissible to a Group 'A' officer of the Central Government drawing an equivalent pay, but he shall not be entitled to receive the Dearness Relief on pension during the period he holds office as such Member;

(ii) receive city compensatory allowance at the same rate as is admissible to a Group 'A' officer drawing an equivalent pay under the Central Government;

(iii) (a) thirty days of earned leave for every year of service and the payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 and the Chairperson shall be the authority competent to sanction leave to the Members.

(b) encashment of fifty per cent of earned leave to his credit at any time.

(iv) subscribe to the Contributory Provident Fund which shall be governed by the Contributory Provident Fund Rules(India), 1962;

(v) travelling allowance and daily allowance for transportation of personal effects while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Appellate Tribunal or on the expiry of his term with the Appellate Tribunal to proceed to his home-town), at the same rates as are admissible to Group 'A' officers of the Central Government drawing equivalent pay;

(vi) the facility of Government accommodation in guest houses or Inspection bungalows run by the Central Government, wherever available, on payment of normal rent at outstations, while on tour, as is admissible to Group "A" Officers of the Central Government drawing equivalent pay:

Provided that where Government accommodation is not available while on domestic official tour, the Member shall be entitled to stay in India Tourism Development Corporation hotels on a reimbursement basis and wherever India Tourism Development Corporation hotels are not available, in other hotels on reimbursement basis; re-imbursement in both cases being limited to lodging charges only, and on a single room occupancy basis;

(vii) leave travel concession at the same rate as admissible to Group 'A' officers of the Central Government drawing an equivalent pay;

(viii) medical treatment and hospital facilities, as provided in the Central Government Health Scheme and at places where the Central Government Health Scheme is not in operation, the Member shall be entitled to facilities as provided in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944;

(ix) undertake official visits abroad with the prior approval of the Minister of the Government of India in-charge of the Department of Telecommunications and after clearance from Ministry of External Affairs on the points relating to political affairs; the daily allowance and provision of hotel accommodation during the period of tour abroad shall be regulated in accordance with the Government instructions as applicable to officers of equal grade in the Government of India; Indian Missions abroad shall take care of arrangements and extend facilities as

admissible to Group "A" officers of the Central Government drawing an equivalent pay;

(x) conveyance facilities as admissible to a Group 'A' officer of the Central Government drawing equivalent pay;

(xi) residential accommodation as admissible to a Group 'A' officer of the Central Government drawing equivalent pay, and on demitting office, the Member shall be entitled to retention of residential accommodation for one month, on the same terms and conditions.

(2) Retirement from Government Service – A person in the service of the Government, on his selection as a Member, shall have to retire from service before entering upon his office as a Member.

**9. Oath of Office and Secrecy: –**

Every person appointed as the Chairperson or a Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy, in Form I and Form II respectively annexed to these Rules.

**10. Declaration of financial or other interest** – Every person, on his appointment as the Chairperson or Member, as the case may be, shall give a declaration in Form III annexed to these rules, to the satisfaction of the Central Government, that he does not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as such Chairperson or Member, as the case may be.

**11. Residuary provision :-**

Matters relating to the terms and conditions of service of the Chairperson or Member with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred by the Appellate Tribunal to the Central Government for its decision.

**12. Powers to relax:-** The Central Government shall have power to relax any provision of these rules with respect to any class or category of persons.

[F. No. 10-11/2000-TCO]

ANIL KUMAR, Jt. Secy.

**FORM – I**  
**(See rule 9)**

Form of Oath of Office for the Chairperson/Members of the Telecom Disputes  
Settlement and Appellate Tribunal

I, \_\_\_\_\_, having been appointed as the Chairperson or/Member (*cross out portion not applicable*) do solemnly affirm and do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chairperson/ Member (*cross out portion not applicable*), of the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal, to the best of my ability, knowledge and judgement, without fear or favour, affection or ill -will.

Dated: \_\_\_\_\_ (Name of the Chairperson/Member)  
TELECOM DISPUTES SETTLEMENT AND APPELLATE TRIBUNAL

**FORM – II**  
**(See rule 9)**

Form of Oath of Secrecy for the Chairperson/Members of the Telecom Disputes  
Settlement and Appellate Tribunal

I, \_\_\_\_\_, having been appointed as the Chairperson/ a Member (*cross out portion not applicable*) do solemnly affirm and swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Chairperson/ a Member (*cross out portion not applicable*) of the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal except as may be required for the due discharge of my duties as the Chairperson/ a Member (*cross out portion not applicable*).

Dated: \_\_\_\_\_ (Name of the Chairperson/Member)  
TELECOM DISPUTES SETTLEMENT AND APPELLATE TRIBUNAL

**FORM – III**  
**(See rule 10)**

**Declaration against acquisition of any adverse financial or other interest**

I, \_\_\_\_\_, having been appointed as the Chairperson/ Member (*cross out portion not applicable*) of the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal, do solemnly affirm and declare that I do not have, nor shall have in future any financial or other interest which is likely to affect prejudicially my functioning as the Chairperson/ Member (*cross out portion not applicable*) of the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal.

Dated: \_\_\_\_\_ (Name of the Chairperson/Member)  
TELECOM DISPUTES SETTLEMENT AND APPELLATE TRIBUNAL

